

वाईएमसीए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने सहायक प्रोफेसर नरेश यादव की इस पहल की साहाना की

स्वच्छ भारत के लिए हर माह दो दिन का वेतन देंगे प्रोफेसर



फरीदाबाद | कार्यालय संचालनाता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुशल भारत-कौशल भारत और स्वच्छ भारत अभियान जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए शहर के प्रोफेसर नरेश यादव ने अनूठी पहल की है। वाईएमसीए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कार्यरत सहायक

प्रोफेसर नरेश यादव ने पूरे सेवाकाल में से हर महीने दो दिन का वेतन इन विकासपारी योजनाओं के लिए देने की घोषणा की है। सरकारी योजनाओं को बढ़ावा दिलें यही इनका उद्देश्य है।

वाईएमसीए विविध विभाग में कार्यरत नरेश यादव ने केन्द्र सरकार की विकास कार्यों से जुड़ी इन योजनाओं को युवाओं और देश के लिए जरूरी बताया। उनके सेवाकाल के दौरान अर्जित होने वाले वेतन से प्रतिमाह दो दिन का वेतन सरकारी कार्यक्रमों की सफलता के लिए अंशदान के रूप में लेने की बात कही।

अनूठी पहल

- मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत हैं नरेश यादव
- प्रतिमाह दो दिन का वेतन सरकारी योजनाओं में दान देंगे



कौशल भारत और स्वच्छ भारत का सपना हो सकता

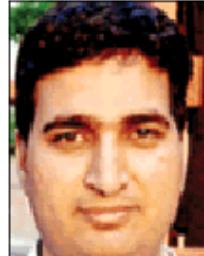
1998 से वाईएमसीए में कार्यरत हैं

प्रो. नरेश यादव ने पांचवीं इंजीनियरिंग कॉलेज, उंचीगढ़ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया है। इसके बाद वर्ष 1998 से वाईएमसीए में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत है। ऐसे में वाईएमसीए जैसे विश्वविद्यालयों का सहयोग जरूरी है।

Dainik Jagran (18.02.2016)

हर माह देंगे दो दिन का वेतन

जासं, फरीदाबाद : वाईएमसीए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद में सहायक प्रोफेसर नरेश यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियानों से इतने प्रभावित हुए कि



प्रतिमाह दो दिन का वेतन केंद्र सरकार के 'कुशल भारत-कौशल भारत' और 'स्वच्छ भारत' अभियान के लिए देने की घोषणा की है। नरेश यादव मूलरूप से सोहना के पास हाजिपुर गांव के रहने वाले हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद 1998 से वह वाईएमसीए यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए किए जा रहे प्रयास और उनकी विकासात्मक सोच से वह बेहद प्रेरित है। वह मानते हैं कि इंजीनियर केवल मशीनों के नहीं बल्कि पूरे देश के निर्माता होते हैं। इसी सोच के कारण उन्होंने देश निर्माण के लिए अपना छोटा सा योगदान दिया है। उनकी दो दिन का वेतन करीब 7 हजार रुपये बैठता है। यह हर महीने अपने आप उनके वेतन में से कटकर केंद्र सरकार के खाते में चला जाएगा। विश्वविद्यालय कुलपति प्रो. दिनेश कुमार ने यादव की पहल की प्रशंसा की।

बुजुर्गों ने थामी डिजिटल साक्षरता की छड़ी

हरेंद्र नागर, फरीदाबाद

वाइएमसीए यूनिवर्सिटी में चल रही डिजिटल साक्षरता कक्षाओं को देखकर कहा जा सकता है कि आधुनिक जमाने के बुजुर्गों को लकड़ी की छड़ी के अलावा आधुनिक तकनीक का भी सहारा चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया से प्रेरित होकर चलाई जा रही इन कक्षाओं में बुजुर्ग युवाओं से अधिक संख्या में पहुंच रहे हैं। 75 साल तक की उम्र के बुजुर्ग भी इन कक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। एक सप्ताह पहले ही यह कक्षाएं शुरू की गई हैं। एक कक्ष में 20 लोग शामिल किए जाते हैं, इनमें से 80 फीसद संख्या बुजुर्गों की होती है।

डिजिटल साक्षरता कक्षाओं में बुजुर्गों की रुचि का कारण वाइएमसीए यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. दिनेश कुमार अग्रवाल बताते हैं कि गैस बुकिंग से लेकर बुढ़ापा पेंशन तक हर सेवा ऑनलाइन हो रही है। बुजुर्गों को इंटरनेट का ज्ञान नहीं होता, इससे वह खुद को असहाय समझते हैं। आज बुजुर्ग किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। इसलिए वह भी इंटरनेट का प्रयोग करना सीखना चाहते हैं ताकि गैस बुकिंग, बुढ़ापा पेंशन हासिल करना, ई-बैंकिंग, रेल रिजर्वेशन, पासपोर्ट, एलपीजी बुकिंग तथा सरकारी ई-सुविधाओं की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि सचना-प्रौद्योगिकी दायरा बढ़ा है। ई-गवर्नेंस से सरकारी सुविधाओं व योजनाओं की पहुंच सीधे आम आदमी तक बनी है। ई-गवर्नेंस का फायदा तभी है जब लोगों के पास बेसिक कंप्यूटर एवं इंटरनेट का ज्ञान हो। अधिकतर युवाओं के पास यह

प्रो. दिनेश कुमार ने बताया कि कक्षाओं



वाइएमसीए यूनिवर्सिटी के कम्यूनिटी कॉलेज में डिजिटल साक्षरता कक्ष में युवाओं के साथ बैठे बुजुर्ग।

जागरण

- ◆ वाइएमसीए यूनिवर्सिटी में चल रहीं कक्षाओं में युवाओं से ज्यादा पहुंच रहे बुजुर्ग
- ◆ एक सप्ताह से चल रहीं कक्षाओं में उपस्थि होने वाले छात्रों में से लगभग 80 प्रतिशत होते हैं बुजुर्ग

ज्ञान होता है मगर बड़ी संख्या में शहर के बुजुर्ग इससे बंचित हैं। उनके लिए यह कक्षाएं वरदान साबित हो रही हैं।